कारवाई के डर से ग्रामीण फरार विस्फोटकों से भरा बोरी फेंका

बड़हरिया (सीवान)। जामो थाना क्षेत्र के अलमापुर गांव में पटाखा निर्माण के दौरान हुए भीषण विस्फोट के बाद पुलिस और प्रशासन ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। अभियान के बाद विस्फोटक से भरा बोला ग्रामीणों द्वारा फेंके जाने की सूचना है। वहीं, कार्रवाई के डर से गांव के कई लोगों के फरार होने की बात सामने आई है। हालांकि, बरामद सामग्री की प्रकृति और मात्रा की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

आलमपुर विस्फोट कांड

गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को अलमापुर गांव में पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में पांच लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद गांव में अवैध पटाखा निर्माण और बारूद के भंडारण को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ दो दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने सभी अंचलाधिकारियों और थानाध्यक्षों को सघन जांच कर अवैध कारोबारियों की पहचान करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जांच के दौरान पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस की भी पड़ताल की जा रही है। अलमापुर में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने की सूचना ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। अब जांच के दौरान यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि विस्फोटक सामग्री कहां रखी गई थी, इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और इस अवैध कारोबार में किन लोगों की संलिप्तता है।

जर्मनी के साथ बढ़ेगा शोध और कारोबार

नयी दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जर्मनी के बर्लिन में भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अब जर्मन कंपनियों के लिए सिर्फ सामान बेचने का बाजार नहीं रह गया है। जर्मनी भारत को मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने के बड़े केंद्र के रूप में देख रहा है। जर्मनी की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की प्रतिभा मिलकर दोनों देशों के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं।

पीयूष गोयल ने विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को देश लौटने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार उद्योग जगत, विश्वविद्यालयों और प्रमुख शोध संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगी। कोशिश होगी कि भारत में ऐसा माहौल तैयार किया जाए, जहां प्रतिभाशाली लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाने के बेहतर अवसर मिलें।

मंत्री ने बताया कि भारतीय



रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में साथ बढ़ने की तैयारी

शोधकर्ताओं से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि वे देश लौटने के लिए किन सुविधाओं की उम्मीद करते हैं। उनके मुताबिक, प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने के लिए केवल अच्छा वेतन देना काफी नहीं है। बेहतर प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण, शोध के लिए जरूरी संसाधन और उद्योगों से जुड़कर काम करने के मौके भी उतने ही जरूरी हैं। गोयल ने कहा कि भारत की युवा आबादी, कुशल पेशेवर और वैज्ञानिक प्रतिभा देश को कई तकनीकी क्षेत्रों में आगे ले जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि उद्योग और शोध संस्थान मिलकर नई तकनीक विकसित करें और उसे बाजार तक पहुंचाएं। उन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, बैटरी, लॉजिस्टिक्स और कृषि को सहयोग के अहम क्षेत्र बताया। बर्लिन दौरे के दौरान गोयल ने जर्मन कंपनियों और शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने जर्मनी के फ्रॉनहोफर संस्थानों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां करीब 22,000 वैज्ञानिक काम करते हैं और इनका बजट दो अरब यूरो से अधिक है।

विरोधियों का तबीयत खराब कर देगी पार्टी : नीरज कुमार

पटना (आससे)। नीरज कुमार ने विरोधियों को लेकर सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने विरोध किया, उनकी तबीयत खराब रहेगी।

शनिवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत में नीरज कुमार ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न हो गया है और इसमें कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। उन्होंने इस चुनाव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति कार्यकर्ताओं के स्नेह और राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ बौद्धिक जनादेश से जोड़ते हुए कहा कि इसका गहरा असर पड़ेगा।

बिहार विधान परिषद चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब सबकी नजर परिणाम पर टिकी है। 27 अक्टूबर को मतों की गिनती होगी। इस बीच चुनाव में जदयू प्रत्याशी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार तथा मोकामा के विधायक अनंत सिंह के बीच की तल्खी चर्चा में है।

कीट-कीस के पदक विजेताओं को २.५ करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि

नयी दिल्ली (आससे)। कीट और कीस ने २०वें एशियाई खेलों और २३वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कुल २.५ करोड़ रुपये की नकद पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्थापक प्रो. अच्युत सामंत ने लहस एंजिल्स ओलंपिक-२०२८ में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की।

संस्थान के ५७ खिलाड़ियों ने जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेलों में २१ पदक जीते, जबकि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में १४ खिलाड़ियों ने पांच पदक हासिल किए। इन उपलब्धियों के साथ खिलाड़ियों ने देश का गौरव बढ़ाया। प्रो. सामंत ने कहा कि शिक्षा और खेल एक-दूसरे के पूरक हैं।

किसी युवा को दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। इसी सोच के तहत कीट और कीस में खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, खुली चयन प्रक्रिया और विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि शुरुआत से ही प्रतिभाओं को निखारकर चौंपियन तैयार करना है। उन्होंने पुरानी कहावत श्खेलोगे-कूदोगे बनोगे खराबश को बदलते हुए संदेश दिया कि खेलों से खिलाड़ी चौंपियन बनते हैं।

पीस बांड पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी : नेहा बोरा

नयी दिल्ली (आससे)। आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने शनिवार को कहा कि वह पीस बान्ड पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका इस्तेमाल लोकतांत्रिक विरोध-प्रदर्शनों को रोकने के लिए किया जा सकता है।

नेहा बोरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संविधान शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार देता है, जबकि पीस बान्ड के जरिये प्रदर्शनकारियों से शांति भंग नहीं करने का आश्वासन मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि आइसा ऐसी कार्रवाई को सामान्य नहीं बनने देगा।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नेहा बोरा की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने पीस बान्ड संबंधी नोटिस को चुनौती दी थी। उन्होंने १६ अक्टूबर को हुए 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए १० हजार रुपये का निजी मुचलका और एक जमानतदार देने संबंधी नोटिस को चुनौती दी थी।

देशभर में ११ करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य हासिल

नयी दिल्ली (आससे)। केंद्र सरकार ने देशभर में ११ करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच महीने पहले हासिल कर लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीडियो संदेश के जरिए यह जानकारी दी।

चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च २०२७ तक ११ करोड़ किसान आईडी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसे २३ अक्टूबर की रात तक पूरा कर लिया गया। उन्होंने कहा कि किसान आईडी से सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके जरिए किसान बैंक ऋण, फसल बीमा, आपदा राहत और अपनी उपज बेचने जैसी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि इस पहल से योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंचाने और आधुनिक तकनीक के जरिए खेती को अधिक सरल व प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।

मतदाता सूची की गड़बड़ियों के लिए साफ्टवेयर को जिम्मेदार ठहराना गलत : जयराम रमेश

नयी दिल्ली (आससे)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में कथित विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए गड़बड़ियों का ठीकरा साफ्टवेयर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। जयराम रमेश ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में दावा किया कि विधान परिषद चुनाव की मतदाता सूची में मतदाताओं और उनके पिता के नाम के स्थान पर आपत्तिजनक और बेतुकी प्रविष्टियां दर्ज थीं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ऐसी गलतियां उत्तर प्रदेश में सामने आई हैं, तो दूसरे चुनावों में ऐसी गड़बड़ियां नहीं होने का दावा कैसे किया जा सकता है।

राहुल गांधी की रैली पर भाजपा हमलावर

नयी दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह जानबूझकर रैली की तारीख बदलने से इनकार कर रहे हैं। उनके मुताबिक, 1 नवंबर को रैली करने से 1984 के सिख विरोधी दंगों की यादें ताजा होंगी और सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। उधर, दिल्ली के व्यापारियों ने भी रैली की तारीख बदलने की मांग की है।



शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी एक सोची-समझी रणनीति के तहत 1 नवंबर को ही रैली करने पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता के इस फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की। प्रसाद ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इसी तारीख पर रैली क्यों करना चाहते हैं और इसके जरिए लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं।

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर और गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को सम्मान देने का उदाहरण दिया। प्रसाद ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के उस बयान को भी याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था, 84 की बात बार-बार क्यों उठाते हो जो हुआ, सो हुआ। इस बीच, दिल्ली के व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर रैली की तारीख बदलने की मांग की है। संगठन के चेयरमैन बृजेश गोयल ने आग्रह किया है कि रामलीला मैदान में होने वाली रैली 10 नवंबर यानी भाई दूज के बाद कराई जाए। व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बाजारों में सबसे ज्यादा खरीदारी होती है और ऐसे समय में रैली से कारोबार प्रभावित हो सकता है।

आजमगढ़ की वोटर लिस्ट में 10 बार विकास यादव

आजमगढ़ (एजेंसी)। आजमगढ़ जिले की वोटर लिस्ट में विकास यादव का नाम 10 बार मिलने के मामले में निर्वाचन आयोग ने ऐक्शन लिया है। जांच के बाद कंप्यूटर ऑपरेटर और पांच बीएलओ(बीएलओ) को मतदाता सूची के काम से हटा दिया गया है। इनके खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं, तत्कालीन दो ईआरओ और एईआरओ के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से पूरे जिले की मतदाता सूचियों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास यादव नाम के युवक को पेश करते हुए आरोप लगाया था कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में उसके नाम पर कई जगह वोट दर्ज हैं। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी। जांच के दौरान विकास यादव नाम की कई प्रविष्टियां सामने आईं। जिनमें एक व्यक्ति का वास्तविक नाम विकास यादव पाया गया, जबकि अन्य 10 लोगों के नाम और विवरण में त्रुटियां मिलीं। इनका विवरण दुरुस्त करने के लिए फॉर्म-8 भरवाया गया है। जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर और पांच बीएलओ की लापरवाही सामने आने के बाद उन्हें मतदाता सूची से जुड़े कार्यों से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर सेवा संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-32 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह का कार्यकाल एक साल बढ़ा

नयी दिल्ली (एजेंसी)। भारत सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के कार्यकाल को एक साल बढ़ा दिया है। अब वह 31 अक्तूबर 2027 तक रक्षा सचिव बने रहेंगे। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब कुछ दिन बाद ही 31 अक्तूबर 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। बता दें, राजेश कुमार सिंह इस पद पर 1 नवंबर 2024 से आसीन हैं। इसके अलावा इस साल 31 मई से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चैयरमैन का पद संभाल रहे हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को सरकार का भरोसेमंद माना जाता है। 1989 बैच में केरलम कैडर के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 2024 में गिरिधर अरमाने की जगह पर 40वें रक्षा सचिव के रूप में यह पद संभाला था। इसके बाद उन्होंने रक्षा विभाग और डीआरडीओ को तेजी से फैसले लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने मिसाइल सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सऊदी जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट्स 7 नवंबर तक टलीं

नयी दिल्ली (एजेंसी)। सऊदी अरब में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की रियाद और दमाम के लिए आने-जाने वाली उड़ानें 7 नवंबर 2026 तक स्थगित रहेंगी। वहीं, जेद्दा के लिए आने-जाने वाली सेवाएं 31 अक्टूबर 2026 तक स्थगित रहेंगी। 24 अक्टूबर 2026 या उससे पहले जारी की गई कन्फर्म बुकिंग के लिए, रीबुकिंग ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। यह लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करके पूरा रिफंड ले सकते हैं। एयर इंडिया के यात्री जो रियाध और दमाम जाने वाले हैं या वहां से लौट गए हैं। जिनकी यात्रा की तारीखें 7 नवंबर 2026 तक हैं, वे उपलब्धता के अनुसार सऊदी अरब के किसी भी ऑपरेशनल एयर इंडिया स्टेशन के लिए एक बार मुफ्त में री-बुकिंग कर सकते हैं। यह 21 नवंबर 2026 तक के लिए मान्य होगा।

प्रथम पृष्ठ का शेष

औद्योगिक विकास की...

गया जिले के डोभी प्रखंड में लगभग1,670 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी विकसित करने की योजना औद्योगिक विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य उद्योगों को एक ही क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने से निवेशकों को उद्योग स्थापित करनेमें सुविधा मिलनेकी उम्मीद है। इससे गया और आसपास के क्षेत्रोंमें औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ रोजगारके नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

कार्यक्रम में आगामी 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 'के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का भी शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी गई। इस पहल के माध्यम से देश और विदेश के निवेशकों को बिहार में निवेश के अवसरों से परिचित कराने तथा बड़े औद्योगिक प्रस्तावों को आकर्षित करने की योजना है।

बिजनेस कनेक्ट जैसे आयोजनों के जरिए सरकार उद्योग जगत और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ाने,निवेश संबंधी समस्याओं को समझने और औद्योगिक परियोजनाओंको आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। कार्यक्रम में आगामी 'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2027 'के कर्टेन रेजर कार्यक्रम का भी शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी गई। इस पहल के माध्यम से देश और विदेश के निवेशकों को बिहार में निवेश के अवसरों से परिचित कराने तथा बड़े औद्योगिक प्रस्तावों को आकर्षित करने की योजना है।

राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और बिहार में विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। उपलब्ध कराई गई जानकारीके अनुसार,निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले स्थानीय उद्योगों के उत्पादों का 25प्रतिशत तक सरकारी खरीद में शामिल करने की घोषणा भी की गई थी।

इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना,उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में औद्योगिक विकास को मजबूत करना है। हालांकि,इस प्रावधान की पात्रता,लागू शर्तों और कार्यान्वयन की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम माँझी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विस अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार, बिजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री संतोष सुमन, विधायक ई कुमार सर्वजीत, ज्योति मांझी, मनोरमा देवी, बीरेन्द्र सिंह, अजय दांगी, रोमित कुमार, उपेंद्र प्रसाद, उदय सिंह, दीपा कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य लोग मौजूद थे।

12 कंपनियों से...

साइंसेज के 1,500 करोड़, एबीआईएस ग्रुप के 600 करोड़, बायोहील एनर्जी के 510 करोड़, जियोफास्ट इंडस्ट्रीज के 500 करोड़ और कुमार आर्गेनिक्स के 300 करोड़ के प्रस्ताव प्रमुख हैं। अन्य सात कंपनियों ने भी निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए।

उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि बीआईएमसीजीएल बिहार को प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनानेकी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमारने बताया कि यहां आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के विकास और निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा।

निवेश प्रस्तावों में मिंट लाइफ साइंसेज की ओर से 1,500 करोड़ रुपये, एबीआईएस ग्रुप की ओर से 600 करोड़, बायोहील एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 510 करोड़ और जियोफास्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से 500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है।

इसके अलावा कुमार आर्गेनिक्स 300 करोड़, जियाना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 206 करोड़, नालंदा आटोमेक प्राइवेट लिमिटेड 120 करोड़, अमरनाथ टेक्सटाइल 110 करोड़ और मां भद्रकाली एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड 95 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। शिवा एग्रो नेचुरल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और वास्तु विहार बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के 51-51 करोड़ तथा कनकलया ज्वेलरी के 50 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी शामिल हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम माँझी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विस अध्यक्ष डा. प्रेम कुमार, बिजेंद्र यादव, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, मंत्री संतोष सुमन, विधायक ई कुमार सर्वजीत, ज्योति मांझी, मनोरमा देवी, बीरेन्द्र सिंह, अजय दांगी, रोमित कुमार, उपेंद्र प्रसाद, उदय सिंह, दीपा कुमारी, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य लोग मौजूद थे।

इसके पूर्व शनिवारको मुख्यमंत्री, बिहार के गया एयरपोर्ट आगमन पर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र, गया, जिला पदाधिकारी, गया, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया एवं नगर पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गया पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को विधिवत गार्ड आफ आनर प्रदान किया गया।

अनंत और उनकी पत्नी...

विधानसभा सदस्यता को भी अविलंब रद्द करने की औपचारिक संसिद्धि/अनुशंसित कार्रवाई की है। इस हाई-प्रोफाइल कार्रवाई की चपेट में केवल अनंत सिंह ही नहीं आए हैं, बल्कि उनके साथ ही पूर्व विधायक नीलम देवी की प्राथमिक सदस्यता को भी दलविरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया है।

उन्हें भी पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाल ही में संपन्न हुए विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जन सुराज समर्थित उम्मीदवार का खुला समर्थन किया था और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। इसी बगावती तेवर और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते जेडीयू ने यह कड़ा कदम उठाया है, जिससे बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है।

जेडीयू बाढ़ जिला अध्यक्ष...

चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार का विरोध करते हुए जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में वोट मांगना महंगा पड़ गया। मतदान के अगले दिन शनिवार शाम को जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया।

जेडीयू नेतृत्व अब अनंत सिंह के समर्थकों को पार्टी में साइडलाइन करने में जुटा हुआ है। विधान परिषद चुनाव के दौरान अनंत सिंह के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जनसुराज कैंडिडेट अनुज सिंह के प्रचार में शामिल हुए थे। ऐसे लोगों पर पार्टी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। जेडीयू के संगठन जिला बाढ़ की पूरी इकाई को भंग करना इसी कार्रवाई का हिस्सा है।

बताया जा रहा है कि जेडीयू बाढ़ जिला इकाई में बड़ी संख्या में अनंत के समर्थक भरे हैं। इसलिए पार्टी अब नये सिरे से यहां नियुक्तियां करेंगी। बाढ़ जिलाध्यक्ष के भी बदले जाने की चर्चा है। मौजूदा जिला अध्यक्ष मयंक राज को पदमुक्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति 7 महीने पहले ही हुई थी।

विप चुनाव के फाइनल...

दर्ज की गई है। अंतिम आंकड़ों के अनुसार, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 74.75 प्रतिशत, सारण में 89.05 प्रतिशत, तिरहुत में 82.99 प्रतिशत और दरभंगा में 85.87 प्रतिशत मतदान पड़े हैं। चारों शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदान 82.85 प्रतिशत रहा। इससे पहले शाम चार बजे तक पटना में 56.89 प्रतिशत, सारण में 87.16 प्रतिशत, तिरहुत में 78.10 प्रतिशत और दरभंगा में 79 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।

चुनाव आयोग ने शाम चार बजे तक के मतदान के आंकड़े जारी करते हुए पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम मतदान प्रतिशत बाद में जारी किया जाएगा। अंतिम आंकड़ों में बढ़ोतरी के पीछे दो संभावित वजहें हो सकती हैं। पहला वोटिंग का निर्धारित समय शाम चार बजे तक था, लेकिन उस समय तक मतदान केंद्रों पर कतार में लगे मतदाताओं को वोट डालने का मौका दिया गया। इसके अलावा दूसरा कारण विवाद हो सकता है।

पटना में वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ा है, जिसका मतलब है कि पटना में मतदान के आखिरी दौर में बड़ी संख्या में वोटर बूथ पर शाम 4 बजे से पहले आकर लाइन में लग गए और उनके वोट से शाम 4 बजे तक के नंबर में सबसे पीछे चल रहा पटना ग्रेजुएट सीट पर सबसे आगे हो गया है। दरअसल, पटना ग्रेजुएट सीट इस चुनाव का मुख्य आकर्षण है, जहां जेडीयू के कैंडिडेट नीरज कुमार को हराने के लिए जेडीयू के ही विधायक अनंत सिंह ने खुली बगावत कर दी है। अनंत सिंह ने यहां जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह के लिए वोट मांगा है।

गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

पांच संवेदकों पर...

सामने आई है। कार्यपालक अभियंताओं और डीएमटी की अनुशंसा के आधार पर संबंधित संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का निर्माण अधूरा छोड़ने के मामले में संवेदक राजेश कुमार को डिबार किया गया है। नालंदा के हरनौत में प्लस टू उच्च विद्यालय भवन का काम पूरा नहीं करने के मामले में कुमार सरोज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अन्य परियोजनाओं में चितरंजन कुमार शर्मा, अविशाक कुमार, अमित कुमार सिंह और अमित रंजन के खिलाफ भी डिबार करने अथवा कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई है। अररिया, शेखपुरा, लखीसराय, कटिहार, शिवहर, किशनगंज और नवादा समेत अन्य जिलों में लंबे समय से अधूरे पड़े निर्माण कार्यों के एकारनामे रद्द करने की प्रक्रिया तेज की गई है। इनमें रिद्धि कंस्ट्रक्शन (अररिया), मेसर्स कादंबिनी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (शेखपुरा), विजय कुमार (लखीसराय), गोपाल कुमार (कटिहार), मेसर्स प्रमोद कंस्ट्रक्शन (नवादा) और विनीत झा (किशनगंज शिक्षा भवन परियोजना) से जुड़े मामले शामिल हैं। संबंधित संवेदकों को नोटिस जारी करने और अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर पांच संवेदकों पर एक प्रतिशत की दर से कुल 73.33 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इनमें मेसर्स हरिओम कंस्ट्रक्शन पर 28.42 लाख, मेसर्स अध्याय इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर 16.30 लाख, मेसर्स अक्षित इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 15.80 लाख, एम.के. गुप्ता पर 11.36 लाख और अजय कुमार पर 1.45 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। इसके अलावा, गंभीर अनियमितता के मामले में शिवांगी कंस्ट्रक्शन का कार्यादेश रद्द कर उसकी जमानत राशि जब्त कर ली गई है।

मैट्रिक-इंटर के रजिस्ट्रेशन...

से अपने यूज़र आई डी एवं पासवर्ड द्वारा 11वीं कक्षा के छूटे हुए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसी प्रकार मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2028 के लिए 9वीं कक्षा के छूटे हुए विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन शिक्षण संस्थान वेबसाइट के माध्यम से अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड द्वारा कर सकेंगे।

4 करोड़ के स्मैक...

पदार्थ मिला। पुलिस ने इसकी अनुमानित कीमत करीब चार करोड़ रुपये बताई है। इसके अतिरिक्त वाहन से दो मोबाइल फोन और सोने जैसी धातु का एक लॉकेट भी बरामद किया गया। मौके से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा स्कॉर्पियो एन वाहन को जब्त कर लिया गया। बरामद मादक पदार्थ की मात्रा और अनुमानित कीमत को देखते हुए पुलिस इस मामले को महत्वपूर्ण कार्रवाई मान रही है। हालांकि, बरामद पदार्थ की अंतिम पहचान और अन्य तथ्यों की पुष्टि संबंधित जांच एवं विधिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों की पहचान इस प्रकार की गई है—रमेश कुमार, पिता ईश्वरी साह, निवासी वार्ड संख्या-14, रक्सौल थाना, जिला पूर्वी चंपारण। संदीप कुमार, पिता बच्चा सिंह, निवासी बहुअरवा, थाना पलनवा, जिला पूर्वी चंपारण। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार संदीप कुमार का रक्सौल थाना कांड संख्या 349/25 में एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक इतिहास दर्ज है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इन पुलिस पदाधिकारियों की रही अहम भूमिका पूरी कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रक्सौल मनीष आनंद के नेतृत्व में की गई। छापेमारी दल में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह दंडाधिकारी गौतम कुमार, पर्यवेक्षी पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक निर्भय कुमार राय, रक्सौल थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक रमेश कुमार महतो, पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार पासवान, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक प्रेम कुमार, सिपाही अजय कुमार, स्ज्ञस्त्र मोतिहारी की टीम तथा रक्सौल थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।